शिक्षा जगत में क्रान्ति– राष्ट्रीय एकता के लिए समुचित शिक्षा-व्यवस्था आवश्यक है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि प्रारम्भ से ही बालक भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में रम जाएं। पाठ्यक्रम का निर्धारण खूब सोच-समझकर किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों में ऐसे अंशों को हटा लिया जाना चाहिए जिनसे फूट, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद की गन्ध आती हो। महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, छात्रों, प्राध्यापकों, आदि में विभिन्न गोष्ठियों, सेमिनारों द्वारा घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए जिससे अलगाव की प्रवृत्तिया कम होंगी और एकता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।

(4) आर्थिक विषमता का उन्मूलन – देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए। सभी प्रकार के विशेषाधिकार वर्गों का अन्त किया जाना चाहिए। अमीरों और गरीबों में बढ़ती हुई खाई को पाटकर यथाशीघ्र आर्थिक विषमता और असन्तोष को दूर किया जाना चाहिए। पिछड़े हुए राज्यों के आर्थिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। तेलंगाना के आन्दोलन से हमें यह सीख ग्रहण करनी चाहिए कि राज्य के भीतर भी कोई भाग या क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित नहीं रखना चाहिए अन्यथा वहां के लोगों में अलगाव की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं।

(5) विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबन्ध- आज भी कई संगठन जनता में विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न करते हैं, हिंसात्मक आन्दोलन का सहारा लेकर देश में अराजकता फैलाते हैं। ऐसे अराजकतावादी हिंसात्मक तत्वों पर यथाशीघ्र नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। लोकतान्त्रिक राजनीति में हिंसा और अराजकता को कोई स्थान और महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार साम्प्रदायिकता, जातीयता और धर्मान्धता का राजनीति में प्रयोग सर्वथा वर्जित होना चाहिए।(6) सशक्त लोकमत का निर्माण - आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचारपत्रों, चलचित्रों, प्रदर्शनियों तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी तत्वों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए तथा भारतीय राष्ट्र की एकता का प्रचार किया जाना चाहिए। यदि सामान्य जनता के हृदय में राष्ट्रीय एकता के भावों का तीव्र प्रस्फुरण होगा तो देश-प्रेम की ऐसी सरिता बहने लगेगी कि वह संकुचित मनोवृत्तियों का परित्याग करके राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

(7) भाषा और धर्म के मामलों में सहिष्णुता प्रो. एम.

एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि “पूरे देश और सभी क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास, भाषा और धर्म के मामलों में सच्चे अर्थोंमें सहिष्णुता तथा जाति प्रथा को समाप्त करने की यदि हो रही हो तो भारत

सशक्त और संगठित देश के रूप में उठ खड़ा होगा।" वस्तुतः अधिकांश झगड़े और तनाव भाषा और धर्म को ही लेकर हुए हैं। अतः भाषागत एवं धर्मगत एकता बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

न विभिन्न प्रदेशों तथा (8) सांस्कृतिक आदान-प्रदान– भाषायी राज्यों के बीच अधिकाधिक मात्रा में सांस्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें भारत का विविध संस्कृतियों का लोगों को पता लग सके।

(9) राजनीतिक दलों की भूमिका हमारे राजनीतिक दल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। यदि सभी राजनीतिक दल संकीर्णता से ऊपर उठकर धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर जनता में उत्तेजना फैलाना छोड़ दें तो राष्ट्रीय एकता की स्थापना में काफी सहयोग मिल सकेगा।

पिछले वर्षों में पंजाब, असम और कश्मीर में जो हालात पैदा हुए वे राजनीति की ही पैदाइश हैं। इन राज्यों के राजनीतिक दलों एवं नेताओं को संकीर्ण क्षेत्रीय मनोवृत्ति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय मुख्यधारा के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन करना होगा।

आर्थिक विकास और एकता

वस्तुतः अनेक वर्षों में देश में जो सीमित आर्थिक विकास हुआ है वह भी भारत की एकता को सन्तुष्ट करने में सहायक ही रहा है। देश के एक भाग में उपलब्ध कच्चा माल दूसरे राज्य की मिलों की जरूरत पूरी करता है। पंजाब का गेहूं और धान केरल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि केरल की कॉफी और काजू पंजाब के लिए। गुजरात का वस्त्र पश्चिम बंगाल की मांग पर उतना ही निर्भर करता है, जितना कि गुजरात को पश्चिम बंगाल में बनने वाली चीजों की जरूरत है। सभी राज्य एक-दूसरे पर बिजली, सिंचाई और भारी उद्योग के मामले में भी निर्भर है। देश के भीतर निष्क्रमण की प्रक्रिया ने भी नगरों को प्रान्तीयता के स्थान पर सर्व भारतीय स्वरूप ही प्रदान कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) ने भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण को पनपाने में ही सहायता दी है। अपने व्यक्तिगत सम्पर्कों से इन्होंने केन्द्र और राज्यों और विभिन्न राज्यों के बीच टकराव को टाला है। देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के आदर्श भी विभिन्न भागों

के लोगों के बीच सम्बन्धों और और सम्पकों को सुदृढ़ ही बनाने वाले सिद्ध होते, किन्तु फिलहाल राजनीति ने ऐसा नहीं होने दिया।